Under the Private Sector Scheme a letter of Intent has been issued to a private entrepreneur to set up such facilities at km. 82 between Hyderabad and Vijayawada on NH 9. The entrepreneur has not so far furnished the detailed drawings for Ministry's approval.

सूती धागे का मूल्य स्थिर किया जाना

1764. **श्री इकबाल सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में तैयार किये गये सूती धागे के मूल्यों को घटाने और स्थिर करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) सूती यार्न (हैंक और कोन यार्न दोनों) की मासिक औसत कीमतों में इस वर्ष के आरंभ से ही गिरावट आने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों को बंद किया जाना

1765. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषरूप से मध्य प्रदेश में, बंद पड़ी हुई कपड़ा मिलों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या मिलों को पुनरुज्जीवित करने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) 31-5-1996 तक की स्थिति के अनुसार आई डी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सूती मानव निर्मित फाइबर मिल बंद नहीं पड़ी है। 141 मिलें तालाबन्दी, हड़ताल तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण अस्थायी रूप से बंद पड़ी थीं तथा 37 मिलें व्यासमापन के अंतर्गत बंद थीं। मध्य प्रदेश में बंद मिलों की संख्या 9 थी।

(ख) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के कार्यसंचालन की जांच करने तथा उनके पुनर्जीवन के लिए यथोचित योजनाएं बनाने तथा उनकी स्वीकृति देने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Programmes for Development of Major Ports

1766. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to implement massive programmes for the development of Paradeep and other Major Ports during the Ninth Five Year Plan;

(b) if so, the details of the developmental activities proposed to be undertaken in Paradeep and other Major Ports during that Plan period;

(c) the estimated cost of those projects;

(d) whether some of those projects are proposed to be implemented by Private sectors; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKATRAMAN): (a) to (c) Yes, Sir. However, no details are available since the 9th Five Year Plan has not yet been finalised.

Separate Human Rights Courts in all States and Union Territories

1767. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any directives have been issued by Government to all States and Union Territories for setting up of separate Human Rights Courts;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of States which have accepted the directives and the States which are yet to give their consent?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) Section 30 of the Protection of Human Rights Act, 1993 provides for specifying a Court of Sessions in each district to be a Human Rights Court to